

## उत्तराखण्ड में रोजगार की संरचना एवं प्रवृत्ति

### सारांश

उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण जिन उम्मीदों के साथ हुआ था उनमें एक महत्वपूर्ण रोजगार का सृजन भी था। इस पेपर में मुख्य रूप से उत्तराखण्ड निर्माण के बाद से श्रम शक्ति, कार्य शक्ति एवं बेरोजगारी की दर में हुए परिवर्तनों एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संरचना में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। तथा पाया गया है कि उत्तराखण्ड निर्माण के बाद से उसके विकास दर, उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय एवं श्रम बल में काफी वृद्धि हुई है। किन्तु इस अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। जिससे बेरोजगारी बढ़ती गई है। साथ ही कृषि जो यहाँ की जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है, इसमें विकास दर एवं रोजगार दर दोनों में गिरावट आई है। रोजगार प्रदान करने में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। रोजगार के दृष्टिकोण से सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों में प्रगति हुई है। इन दोनों ही क्षेत्रों में विकास दर में भी कृषि क्षेत्र की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फ़ैक्ट्री एवं खनन के क्षेत्र में भी रोजगार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

**मुख्य शब्द** : श्रमशक्ति, श्रम सहभागिता, रोजगार संरचना

### प्रस्तावना

किसी भी देश में रोजगार का आकार बहुत कुछ उसके विकास के स्तर पर निर्भर करता है। जब अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर अग्रसर होता है तो रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। इस संबन्ध में उत्तराखण्ड की बात करें तो उत्तराखण्ड राज्य भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में 9 नवम्बर 2000 में 13 जिलों के साथ अस्तित्व में आया। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 8.48 मिलियन, प्रतिव्यक्ति आय 19,457 (2001-02 में), निर्धनता के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात 43.49 प्रतिशत, जनसंख्या का घनत्व 159 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि० मी०, लिंग अनुपात 964 एवं सारक्षता दर 72.2 प्रतिशत थी। 2001 की स्थिति के अनुसार उत्तराखण्ड के विकास दर में कृषि का योगदान 25.5 प्रतिशत, उद्योगों का 23 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 51.5 प्रतिशत था। जबकि इन विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशतकृषि में 68.6, विनिर्माण में 43.3, गैर विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 एवं सेवा क्षेत्र में 19.6 था। इस आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ जिस उत्तराखण्ड राज्य की शुरुआत हुई वह आज आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत के कई राज्यों से काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है हम इस पेपर में देखने का प्रयास करेंगे।

### उद्देश्य

इस पेपर का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड में रोजगार की प्रवृत्ति एवं संरचना में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना है।

### शोध विधि

यह पेपर द्वितीयक समंक पर आधारित है जो सांख्यिकी डायरी, NSSO के विभिन्न रिपोर्ट, इन्टरनेट, शोधपत्रों एवं किताबों से एकत्रित किए गये हैं।

आर्थिक विकास में पूर्ण रोजगार एक चुनौती है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए ताकि उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त हो सके। यह तभी संभव है जब श्रम बल में वृद्धि के अनुपात में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास हो। इस परिपेक्ष्य में हम देखते हैं कि उत्तराखण्ड के प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 2001-02 से लगातार वृद्धि हुई है। यदि 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर देखें तो प्रारंभिक वर्षों की अपेक्षा 2010-11 एवं 2012-13 में GSDP में थोड़ी कम वृद्धि हुई है। 2005-06 से 2012-13 में उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर औसत रूप से जहाँ 12.3 प्रतिशतकी वृद्धि हुई है वहीं सम्पूर्ण भारत में यह वृद्धि दर इस दौरान 8.02 प्रतिशत है। जबकि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य उत्पाद में भी 2001-02 से 2012-13 तक लगातार वृद्धि हुई

### नीलू कुमारी

असिस्टेंट प्रोफेसर,

अर्थशास्त्र विभाग,

वी० श० के० च० राजकीय

महाविद्यालय,

डाकपत्थर, विकासनगर

देहरादून

है और चालू मूल्यों पर देखें तो यह लगभग छः गुनी हो गई है। इसे हमें आगे तालिका 1 एवं तालिका 2 में देख सकते हैं:-

तालिका : 1

चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	उत्तराखण्ड	भारत
2001-02	16232	17782
2002-03	18836	18885
2006-07	35111	31206
2007-08	42619	35825
2008-09	50657	40775
2009-10	62764	46249
2010-11	72217	54151
2011-12	79940	61564
2012-13	90843	68747

तालिका : 2

2004-05 के स्थिर मूल्यों पर GSDP की वृद्धि दर(%में)

वर्ष	उत्तराखण्ड	सम्पूर्ण भारतवर्ष
2007-08	18.12	9.32
2008-09	12.65	6.72
2009-10	18.13	8.54
2010-11	9.94	9.32
2011-12	5.28	6.21
2012-13	6.87	4.96
औसत वृद्धि दर 2005-06 से 2012-13	12.30	8.02

स्रोत: योजना आयोग का उत्तराखण्ड वार्षिक योजना 2013-14 [www.planningcommission.nic.in](http://www.planningcommission.nic.in) (state planning commission)

उत्पाद के साथ-साथ इस अवधि में उत्तराखण्ड की साक्षरता दर भी 72.2 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं में यह प्रतिशत 71 है जो 2001 में 60.26 प्रतिशत थी। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 88 है। भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन कृषि के विकास दर में इस अवधि में वांछित प्रगति नहीं हुई है जिस कारण से कृषि क्षेत्र के रोजगार में भी कमी आई है। कृषि में वृद्धि दर 2000-01 में 6.60 थी जो विभिन्न वर्षों में उतार चढ़ाव के साथ 2013-14 में 4.12 प्रतिशत हो गई। इस बीच कई वर्षों में वृद्धि दर ऋणात्मक भी रही है। जिसमें मुख्य रूप से 2001-02, 2005-06 एवं 2008-09 का वर्ष है। कुल मिलाकर 2000-01 से 2013-14 तक कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि 2.84 प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय औसत 3.97 प्रतिशत से कम है। इसे हम निम्न तालिका 3 में देख सकते हैं:-

तालिका : 3

उत्तराखण्ड एवं भारतवर्ष में 2000-01 से 2013-14 तक कृषि की वृद्धि दर

वर्ष	उत्तराखण्ड	सम्पूर्ण भारतवर्ष
2000-01	6.60	-0.25
2001-02	-5.44	6.25
2002-03	4.29	-7.24
2003-04	4.87	9.96
2004-05	5.96	1.60
2005-06	-3.22	5.14
2006-07	4.66	4.16
2007-08	2.09	5.80
2008-09	-3.66	0.09
2009-10	9.63	0.81
2010-11	4.38	8.60
2011-12	4.01	5.02
2012-13	3.53	1.42
2013-14	4.12	4.71
2005-06 से 2013-14 तक औसत वृद्धि दर	2.84	3.97

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (31-10-2014 के अनुसार)

Databook for pc, 22<sup>nd</sup> December 2014

रोजगार की प्रवृत्तियाँ (Employment Trends)

रोजगार प्रवृत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त होती है। रोजगार प्रवृत्तियों के विषलेषण के लिए हमें श्रम शक्ति, कार्य शक्ति एवं बेरोजगारी की दर में हुए परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। श्रम शक्ति (Labour Force) किसी देश या राज्य में श्रम की पूर्ति को बताता है जो या तो रोजगार में लगा है या तो बेरोजगार है किन्तु रोजगार की तलाष में है। जिन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है वे कार्य शक्ति (Work Force) का हिस्सा माने जाते हैं। यानि "कार्य शक्ति" वह संख्या है जो "श्रम शक्ति" का एक हिस्सा है। दूसरा वर्ग "श्रम शक्ति" से बाहर लोगों का है। इसमें वे लोग होते हैं जो रोजगार की तलाष में नहीं हैं। जैसे, छात्र, भिखारी, अक्षम व्यक्ति, किराया या पेंशन प्राप्त करके जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति इत्यादि। "श्रम शक्ति" में से जिन लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है जबकि वे इसके लिए योग्यता एवं इच्छा रखते हैं तो वे बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं।

इस दृष्टिकोण से अगर हम उत्तराखण्ड को देखें तो तालिका 4 के अनुसार उत्तराखण्ड में भारत की तरह ही पुरुषों की कार्य सहभागिता दर में 1999-2000 की अपेक्षा 2011-12 में वृद्धि हुई है। जबकि महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में इस अवधि में गिरावट आई है।

तालिका : 4

उत्तराखण्ड एवं भारत में कार्य सहभागिता दर(UPSS)

वर्ष	उत्तराखण्ड			भारत		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1999-2000	38.58	43.57	33.75	39.67	52.73	25.99
2004-05	45.57	51.89	39.55	42.01	54.69	28.67
2011-12	39.20	70.40	9.30	—	—	—

स्रोत : NSSO household unit record data on employment and unemployment, various rounds and Annual Health Survey 2011-12

यदि पहाड़ी एवं मैदानी जिलों में देखें तो तालिका 5 के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर में 2001 की अपेक्षा 2011 में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में

तालिका : 5

उत्तराखण्ड में 2001 एवं 2011 में पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर

क्षेत्र		2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
पहाड़ी	कुल	42.3	4.7	40.0	31.4	62.0	5.1
	ग्रामीण	44.3	44.1	44.5	30.3	61.3	5.4
	शहरी	30.4	47.6	9.1	40.2	60.6	10.2
मैदानी	कुल	31.4	47.9	13.1	44.5	75.4	11.1
	ग्रामीण	33.5	48.3	17.4	39.5	74.6	9.2
	शहरी	28.7	47.3	7.2	46.3	76.5	13.3
उत्तराखण्ड	कुल	38.4	45.9	30.8	39.2	70.5	9.3
	ग्रामीण	41.4	45.3	37.6	36.7	68.5	7.6
	शहरी	29.3	47.4	7.9	45.0	74.6	13.4

स्रोत: Calculated on the basis of population census 2001 and Annual Health Summary 2011-12

यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखण्ड में 2001 की तुलना में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कार्य सहभागिता दर लगभग समान ही रही है जबकि महिलाओं की WPR में इस दौरान गिरावट आई है। जबकि शहर में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की कार्य सहभागिता दर में 2001 की तुलना में 2011-12 में वृद्धि हुई है। समग्र रूप में इस अवधि में पुरुषों की WPR बढ़ी है जबकि महिलाओं की WPR घट गई है।

आयुवर्ग के आधार पर देखने से 1999-2000 की तुलना में 2011-12 में ग्रामीण पुरुषों में जहाँ 30-43, 35-39, 50-54 एवं 60-64 आयु वर्ग के WPR में वृद्धि हुई है वहीं 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 45-49 एवं 55-59 आयुवर्ग की स्थिति लगभग समान ही रही है। महिलाओं के WPR हर उम्र वर्ग में उक्त अवधि में गिरावट आई है। इसे हम तालिका 6 में देख सकते हैं।

तालिका : 6

Age-Wise WPR (UPSS) in 1999-2000 to 2011-12

Age group (Rural Male)	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and above	all
1999-2000	0.00	3.3	21.4	63.3	96.30	97.90	98.50	100.0	100.0	89.75	98.00	56.3	-	43.6
2004-05	0.00	5.3	33.7	70.28	90.20	97.50	97.50	99.5	98.06	95.85	92.38	78.1	-	51.37
2011-12	0.00	0.20	11.50	46.20	85.5	98.6	98.8	99.1	98.0	97.0	86.4	62.5	24.4	43.9

Age group (Rural Female)	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and above	all
1999-2000	0.00	4.3	26.2	72.7	74.3	71.1	76.5	80.7	84.3	81.2	61.0	41.2	-	41.6
2004-05	0.00	5.2	45.7	77.5	79.5	81.1	77.5	75.2	77.0	78.8	87.4	55.2	-	46.6
2011-12	0.00	1.2	6.9	23.9	35.7	37.7	39.3	46.9	39.1	37.7	33.4	16.5	6.9	20.8

Source: Various Rounds of NSSO

श्रम बल का तीसरा महत्वपूर्ण मापदण्ड बेरोजगारी की दर है। तालिका 7 के अनुसार उत्तराखण्ड में 2004-05 की तुलना में 2009-10 एवं 2011-12 में ग्रामीण बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि हुई है। जबकि शहरी बेरोजगारी की दर लगभग समान ही रही है। हालांकि पूरे

भारतवर्ष की तुलना में देखे तो इस अवधि में भारत की औसत बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग समान है जबकि शहरी बेरोजगारी की दर में थोड़ी कमी आई है। उत्तराखण्ड में बेरोजगारी की दर 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्र में 1.3 से बढ़कर 2009-10 एवं 2011-12 में क्रमशः 5.4,

2.9 एवं 5.3 प्रतिशत रही है लेकिन शहरी एवं ग्रामीण दोनों बेरोजगारी की दर भारतवर्ष की तुलना में ज्यादा है।

तालिका : 7

उत्तराखण्ड एवं भारतवर्ष में Usual Status के आधार पर बेरोजगारी दर

क्षेत्र	2004-05		2009-10		2011-12	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
उत्तराखण्ड	1.3	5.4	1.6	2.9	2.5	5.3
भारतवर्ष	1.7	4.5	1.6	3.4	1.7	3.4

Source: NSSO Reports 2004-05, 2009-10, 2011-12

रोजगार की संरचना

रोजगार की संरचना का अध्ययन करने के लिए व्यवसाय के अनुसार रोजगार का वितरण एवं शहरी एवं ग्रामीण रोजगार की प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक है। विकास में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के योगदान में 2001-02 से 2011-12 के दौरान काफी परिवर्तन हुए हैं। 2001-02 में जहाँ कृषि क्षेत्र का विकास में योगदान 25.5 प्रतिशत एवं उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 23.0 प्रतिशत एवं 51.5 प्रतिशत था वह 2011-12 में क्रमशः 11.3 प्रतिशत, 34.4 प्रतिशत एवं 54.3 प्रतिशत हो गया। यानि विकास में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी आई है जबकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है। इसकी तुलना यदि भारतवर्ष से करें तो यहाँ भी कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी एवं सेवा क्षेत्र के योगदान में काफी वृद्धि हुई है। इसे हम तालिका 8 में देख सकते हैं।

तालिका : 8

विकास में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का प्रतिशत

क्षेत्र ↓ / वर्ष →	2001-02		2011-12	
	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत
कृषि	25.5	22.3	11.3	2.9
उद्योग	23.0	27.3	34.4	24.9
सेवा	51.5	50.4	54.3	59.0

विकास में योगदान के अनुरूप ही इन विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के सृजन दर में परिवर्तन हुए हैं। कृषि क्षेत्र में 2004-05 में 2.73 मिलियन लोग (68.6 प्रतिशत) रोजगार में लगे हुए थे जो घटकर 2009-10 में 2.41 मिलियन (60.6 प्रतिशत) हो गया। जबकि विनिर्माण, गैर निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में इसी अवधि में रोजगार क्रमशः 0.17 मिलियन (4.3 प्रतिशत) 0.3 मिलियन (7.5 प्रतिशत) एवं 0.78 मिलियन (19.6 प्रतिशत) से बढ़कर क्रमशः 0.25 मिलियन (6.3 प्रतिशत), 0.47 मिलियन (11.8 प्रतिशत) एवं 0.85 मिलियन (21.4 प्रतिशत) हो गया। इन क्षेत्रों में रोजगार में परिवर्तन को हम निम्न तालिका 9 में एवं 10 में देख सकते हैं:-

तालिका : 9

प्रमुख क्षेत्रों में निरपेक्ष रोजगार (मिलियन में) (2004-05, 2009-10)

क्रम0 सं0	क्षेत्र	2004-05	2009-10
1.	कृषि	2.73	2.41
2.	विनिर्माण	0.17	0.25
3.	गैरनिर्माण	0.3	0.47
4.	सेवा	0.78	0.85
	<b>कुल</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>

तालिका : 10

प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार का प्रतिशत एवं रोजगार में परिवर्तन, (2004-2010)

क्रम0 सं0	क्षेत्र	रोजगार का प्रतिशत		रोजगार के अंश में परिवर्तन
		2004	2009	2004-2010
1.	कृषि	68.6	60.6	-8.0
2.	विनिर्माण	4.3	6.3	2.0
3.	गैरनिर्माण	7.5	11.8	4.3
4.	सेवा	19.6	21.4	1.8
	<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Source: Summary Record of the working group on Employment planing and policy for the twelfth five year plan (2012-17)

तालिका : 11

प्रमुख क्षेत्रों में 1999-2000 से 2010-11 में उत्तराखण्ड में रोजगार के अंश में परिवर्तन

क्र0 सं0	क्षेत्र/उद्योग	1999-2000	2010-11
1.	कृषि एवं वन	79.50	33.5
2.	खनिज	0.0	0.3
3.	विनिर्माण	3.9	11.6
4.	बिजली	0.2	0.7
5.	निर्माण	7.6	20.9
6.	व्यापार	2.0	10.2
7.	यातायात	2.0	2.7
8.	वित्तीय सेवायें	0.5	0.7
9.	समुदायिक एवं अन्य सेवायें	4.3	19.4
10.	<b>कुल</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Source: NSSO, Household Unit Record Data for 38<sup>th</sup>, 43<sup>rd</sup>, 50<sup>th</sup> and 55<sup>th</sup> rounds and Labour bureau, Govt of India.

तालिका 11 के अनुसार 1999-2000 की तुलना में 2010-11 में कृषि एवं वन क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत घटकर 79.30 से 33.5 हो गया है जो आधे से भी कम है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 3.49 से लगभग तीन गुना बढ़कर 11.6 हो गया है। इसी अवधि में निर्माण में 7.61 से बढ़कर 20.9 एवं सामुदायिक एवं अन्य सेवाओं में 4.3 से बढ़कर 19.4 हो गया है। खनिज, यातायात एवं वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत लगभग समान ही रहा है

तालिका : 12

उत्तराखण्ड में 2001 एवं 2011-12 में रोजगार एवं बेरोजगारी से सम्बन्धित विभिन्न संकेतक (Usual Status)

क्षेत्र/ संकेतक	2001			2011-12		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
<b>कुल</b>						
श्रम बल	40.7	49.6	31.3	39.3	49.3	29.0
कार्य बल	38.4	45.9	30.8	36.1	46.1	25.2

बेरोजगार	2.2	3.7	0.4	3.2	2.7	3.8
<b>ग्रामीण</b>						
श्रम बल	43.4	49.2	37.7	40.6	47.9	32.9
कार्य बल	41.4	45.3	37.6	38.1	45.2	30.8
बेरोजगार	1.9	3.8	0.1	2.5	2.7	2.1
<b>शहरी</b>						
श्रम बल	32.8	50.8	12.0	35.8	53.1	28.6
कार्य बल	29.3	47.4	7.9	30.5	50.6	8.6
बेरोजगार	3.4	3.3	4.1	5.3	2.5	20.0

**Source: Calculated from Population census 2001 (Excludes Haridwar district) and NSSO 68<sup>th</sup> Round (July 2011-june2012)**

इस तालिका में 2001 से 2011-12 में श्रम बल, कार्य बल एवं बेरोजगारी की दर को दिखाया गया है। पुरुषों में ग्रामीण क्षेत्र में इस अवधि में श्रम बल एवं कार्य बल दोनों में मामूली कमी आई है जिससे बेरोजगारी की दर (3.8 से घटकर 2.7) में थोड़ी कमी हुई है। जबकि शहरी पुरुषों में श्रम बल एवं कार्य बल दोनों में वृद्धि हुई है परन्तु कुल मिलाकर बेरोजगारी दर कम है। महिलाओं में ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल की अपेक्षा कार्य बल में काफी गिरावट आई है जिससे बेरोजगारी की दर (0.4 से बढ़कर 3.8) बढ़ गई है। शहरी क्षेत्रों में भी श्रम बल में जितनी वृद्धि हुई है उससे काफी कम अनुपात में कार्य बल में वृद्धि हुई है। जिसके कारण बेरोजगारी की दर (3.3 से बढ़कर 20.0) काफी बढ़ गई है। कुल मिलाकर श्रम बल के अनुपात में कार्य बल में कम वृद्धि हुई है इस अवधि में जिस कारण बेरोजगारी (2.2 से 3.2) में वृद्धि हुई है।

#### निष्कर्ष

किसी भी देश में रोजगार का आकार बहुत कुछ उसके विकास के स्तर पर निर्भर करता है। किन्तु उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की प्रगति पर गौर करने से पता चलता है कि यहाँ 2001 से 2012-13 तक जिस अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय एवं शिक्षा का विकास हुआ है उस अनुपात में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। इसका एक मुख्य कारण कृषि, जो भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके विकास दर एवं रोजगार दर दोनों में गिरावट का आना है। 2001 की अपेक्षा 2011-12 में कृषि क्षेत्र में रोजगार में -36.0 की गिरावट आई है। खनिज (0.3), यातायात (0.7) एवं वित्तीय सेवाओं (0.2) के क्षेत्र में भी रोजगार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि विनिर्माण (7.7), निर्माण (13.3), व्यापार (8.2) एवं सामुदायिक तथा अन्य सेवाओं (15.1) के क्षेत्र में रोजगार में प्रगति अवश्य हुई है। कृषि के अतिरिक्त इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जितनी रोजगार में वृद्धि हुई है लगभग उतनी अकेले कृषि क्षेत्र के रोजगार में कमी आई है।

रोजगार वृद्धि की प्रवृत्तियों को देखने से पता चलता है कि 2001 की तुलना में 2011-12 में श्रम बल में वृद्धि के अनुपात में कार्य बल में कम वृद्धि हुई है जिससे बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की कार्यशक्ति में इस दौरान ज्यादा कमी आई है। जिस कारण महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बेरोजगारी की

दर ज्यादा बढ़ी है। यह वृद्धि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रही है। कुल मिलाकर 2001 की अपेक्षा 2011-12 में बेरोजगारी (2.28 से बढ़कर 3.8) की दर में वृद्धि हुई है।

#### सुझाव

कृषि जो उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके विकास पर जोर देना आवश्यक है। क्योंकि आज भी लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इससे कृषि के विकास के साथ-साथ इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। क्योंकि कई उद्योगों का विकास भी कृषि पर निर्भर है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए कृषि की ओर प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। क्यों कि कृषि के विकास दर में इस अवधि में जो गिरावट आई है इसे देखते हुए कृषि क्षेत्र उपेक्षित दिखाई देता है। जबकि इस क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएँ हैं।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, एस. के. एवं पुरी. वी. के, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिकेशन हाउस, मुम्बई, 28 वाँ संस्करण 2016, पृ-128-154
2. Mamgain, Ravindra P, Growth, "Poverty and Employment in Uttarakhand".
3. NSSO Various Rounds Report
4. सांख्यिकी डायरी, उत्तराखण्ड 2010-11
5. Rural Non-Faum sector Employment in Uttarakhand: Patterns and Trends, Chapter-IV
6. UPUEA Economic Journal oct, 2012